



भारत की वैश्विक स्थिति को आकार देने में लघु, कुटीर एवं मध्यम वर्ग उद्योगों का योगदान (उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में)

डॉ० सुनील दत्त¹* और डॉ० संतोश कुमार आर्य¹

¹ असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एम० बी० राज० स्नात० महा० हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड, भारत

*Correspondence Author: डॉ० सुनील दत्त

Received 1 Apr 2026; Accepted 12 May 2026; Published 29 May 2026

DOI: <https://doi.org/10.64171/JSRD.5.S3.51-55>

सारांश

आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ने अपने आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने हेतु अनेक नवीन नीतिगत पहलें की हैं। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्राकृतिक संसाधनों के कारण उत्तराखंड ने पर्यटन, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन क्षेत्रों के विकास ने, न केवल राज्य की आंतरिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है, बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके योगदान को सशक्त किया है। विगत वर्षों में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। जो राज्य की आर्थिक स्थिरता एवं विकासशील प्रवृत्ति को दर्शाती है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या में हुई वृद्धि से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं, जिससे स्थानीय जनसंख्या की आय एवं जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। विशेष रूप से पर्यटन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। जिसने सेवा क्षेत्र के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई है। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर उत्पादन क्षमता को बढ़ाना व स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों की सशक्त बनाना है। उत्तराखंड में इन नीतियों के क्रियान्वयन से कृषि-आधारित उद्योगों, हस्तशिल्प तथा स्वयं सहायता समूहों को विशेष बढ़ावा मिला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड ने आत्मनिर्भर भारत की सोच को अपनाते हुए अपनी आर्थिक संरचना को नई दिशा प्रदान की है। राज्य की पारंपरिक क्षमताओं एवं आधुनिक विकास रणनीतियों के समन्वय से उत्तराखंड न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आत्मनिर्भर विकास के एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में उभर रहा है।

मूलशब्द: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, रोजगार सृजन, मुद्रा अर्जन, आत्मनिर्भर भारत

परिचय

भारत का सम्पूर्ण विकास उसके कुटीर उद्योगों तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। नीति आयोग के अनुसार ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार शिला हैं। जिनकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। लघु एवं कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये कम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। चूंकि इन उद्योगों में श्रम- प्रधान तकनीकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बरोजगारी की समस्याओं को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। कुटीर उद्योगों में अधिकांश कार्य हस्तनिर्मित होता है। जिससे पारंपरिक कौशल एवं कलात्मकता को संरक्षण मिलता है। हस्तशिल्प, हथकरघा, सूती एवं ऊनी वस्त्रों पर कढ़ाई, बांस/बेंत की टोकरियाँ, मिट्टी के बर्तन, अगरबत्ती, मोमबत्ती, चमड़े के उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण (अचार, पापड़) शामिल हैं। तथा हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुएँ आभूषण तथा अन्य घरेलू मॉग को पूरा करते हैं। बल्कि निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जन में भी योगदान देते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना शीघ्र की जा सकती है। तथा इनमें उत्पादन प्रारंभ होने में अधिक समय नहीं लगता। इन उद्योगों का विकास स्थानीय संसाधनों एवं श्रम पर आधारित होता है। जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है। साथ ही कृषि क्षेत्र में पूर्ण या आंशिक रूप से बेरोजगार जनसंख्या को वैकल्पिक

रोजगार उपलब्ध कराने का यह एक प्रभावी साधन है इस प्रकार लघु एवं कुटीर उद्योग भारत के समावेशी विकास रोजगार सृजन तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तराखंड के औद्योगिक परिदृश्य में यह क्षेत्र श्रम प्रधान स्वरूप एवं उच्च रोजगार क्षमता के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य की आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। देखा गया है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1•1 से 1•3 प्रतिशत और कुल निर्यात में 2017-18 के अनुसार 0•48 प्रतिशत की भागीदारी निभाते हैं। यह भी देखा गया है कि कृषि क्षेत्र के बाद MSME क्षेत्र ही सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। जिसके माध्यम से लगभग 4 लाख से लेकर 20 लाख तक के लोगो को आजीविका के अवसर प्राप्त है। राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से MSME क्षेत्र की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण औद्योगीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र को सुधार-पूर्व तथा सुधार-पश्चात दोनों ही अवधियों में निरंतर प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

- जीडीपी में राज्य का योगदान 1•143 प्रतिशत दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर 4,29,308 करोड़ होने का अनुमान है।
- विकास दर 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 7•6 प्रतिशत (स्थिर कीमतों पर) की वृद्धि का अनुमान है। 2023-24 के अनुसार सेवा क्षेत्र 43 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र का 10 प्रतिशत जीडीपी में योगदान है।

उत्तराखण्ड राज्य में पहले से संचालित SMSE उद्योगों का योगदान राज्य की आर्थिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ये उद्योग केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य की औद्योगिक संरचना और अधिक सशक्त होगी। उत्तराखण्ड के भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए MSME क्षेत्र में फार्मास्युटिकल, टिबर उद्योग, कागज उद्योग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे गतिविधियों के लिए आपार संभावनाएं हैं। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में यह उद्योग स्थानीय प्राकृतिक ससाधनों पर आधारित होकर प्रभावी रूप से विकसित किए जा सकते हैं। इन उद्योगों के विस्तार से न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए उनके निवास स्थान के निकट रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे पलायन की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। यह क्षेत्र कम पूंजी में अधिक लोगों को काम देने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे आर्थिक विकास का मजबूत आधार माना जाता है। सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं और सहायतस कार्यक्रमों के माध्यम से इन उद्यमों को प्रोत्साहित करती है।

- कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इन उद्योगों में कम निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे व्यापारी और स्थानीय लोग भी आसानी से अपनी ईकाइयों स्थापित कर सकते हैं। यही कारण है कि इन की संख्या देश में काफी अधिक है।
- ये उद्योग राज्य के उत्पादन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके माध्यम से दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। जैसे – फल प्रसंस्करण, जडी-बूटी, जैविक उत्पाद, फर्नीचर, स्टेशनरी, घरेलू सामान, प्लास्टिक सामग्री, रबर बस्तुएँ, पैकेजिंग सामग्री, खाद्य पदार्थ आदि। इस प्रकार के उद्योग आम जनता की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
 - पर्यटन आधारित व्यवसाय: होमस्टे, साहसिक खेल (रिवर राफ्टिंग) के उपकरण, आतिथ्य सेवाएँ।
 - विनिर्माण क्षेत्र: ऑटो पार्ट्स, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल।
 - नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र: सोलर पैनल और सोलर ऊर्जा से संबंधित छोटी इकाइयाँ।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाते हैं और स्थानीय संसाधनों व श्रम शक्ति का प्रभावी उपयोग करते हैं। ये उद्योग क्षेत्रीय संतुलित विकास में सहायक होते हैं। और देश के किसी भी भाग में स्थापित किए जा सकते हैं।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

कुमार अखिलेश (2020): ने अपने शोध अध्ययन भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति व चुनौतियाँ एक अध्ययन में पाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रही है। यह लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। कृषि के बाद यह दूसरा क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करता है। इसके अलावा यह आय में वृद्धि के साथ-साथ आय वितरण की असमानताओं को कम करती है। जो पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है।

भौली व अन्य (2020): ने अपने अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के योगदान में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि SMSE का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है यह भारतीयों के समावेशी विकास, कुल निर्यात, निर्यात में बढ़ोत्तरी भारत के हरित विकास व आर्थिक विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

यादव नंद किशोर (2023): ने अपने अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME के महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद एमएसएमई क्षेत्र की कई समस्याएँ हैं जिसका सामना एमएसएमई क्षेत्र कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर पर और स्थानीय स्तर पर वित्त व्यवस्था, करना, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना कम ब्याज की असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

उपाध्याय डॉ० वीना (2024): इनके शोध के अनुसार भारत के संतुलित आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। कृषि उत्पादों के भंडारण प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण उद्योग तथा आधारभूत संरचना का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना ग्राम स्तर पर होने से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण-शहरी पलायन की समस्या में कमी आएगी।

अध्ययन के उद्देश्य

- उत्तराखण्ड राज्य में MSME क्षेत्र में विकास एवं वर्तमान स्थिति का समग्र अध्ययन करना।
- उत्तराखण्ड में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा राज्य के रोजगार सृजन, आय वृद्धि एवं औद्योगिक विकास में दिए जा रहे योगदान का अध्ययन करना।
- MSME क्षेत्र के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के सुदृढीकरण और सतत विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध कार्यविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त समंको पर आधारित है। इन समंको का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं, प्रतिष्ठित जर्नलों, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार स्रोतों से लिया गया है। इस शोध पत्र में MSME क्षेत्र के विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान का अध्ययन किया गया है। साथ में एमएसएमई का कुल रोजगार सृजन में कितनी भूमिका है। उसको विस्तारपूर्वक लिखा गया है।

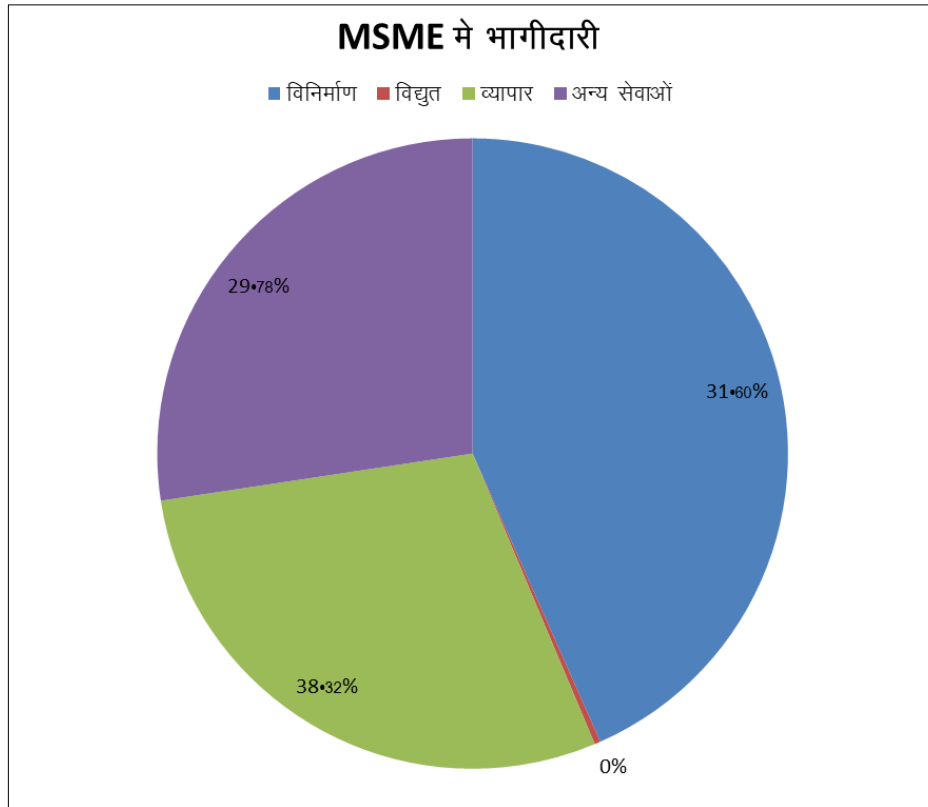
रोजगार में MSME योगदान

वर्ष 2018-19 के अग्रिम अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें चालू तथा मूल्यों पर राज्य की वृद्धि दर क्रमशः 10.34 तथा 7.03 अनुमानित है। अतः आर्थिक विकास की दर 7.03 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। उक्त अनुमान आगामी वर्षों में नवीन आंकड़ों की उपलब्धता होने की सम्भावना है। जो निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 1

क्रियाविधि की श्रेणी	रोजगार (लाख में)			प्रतिशत भागीदारी
	ग्रामीण	भाहरी	कुल	
विनिर्माण	385*64	276*45	662*09	31*60
विद्युत	2*66	3*56	6*22	0*30
व्यापार	290*65	512*05	802*7	38*32
अन्य सेवाओं	280*43	343*52	623*95	29*78
कुल	959*38	1035*58	2094*96	100 /

स्रोत- द्वितीय समंक



ग्राफ संख्या- 1

तालिका संख्या 1 तथा ग्राफ संख्या 1 के आधार पर यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कि MSME क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी लगभग 33 प्रतिशत है। जब कि व्यापार क्षेत्र का योगदान लगभग 33*16 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30*42 प्रतिशत पाई गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है। कि MSME क्षेत्र के माध्यम से 20 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। वही डैडम् क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था ःवृद्धि में लगभग 13-13*1 प्रतिशत के बीच आँका गया है। जो इसकी उपयोगिता को दर्शाता है।

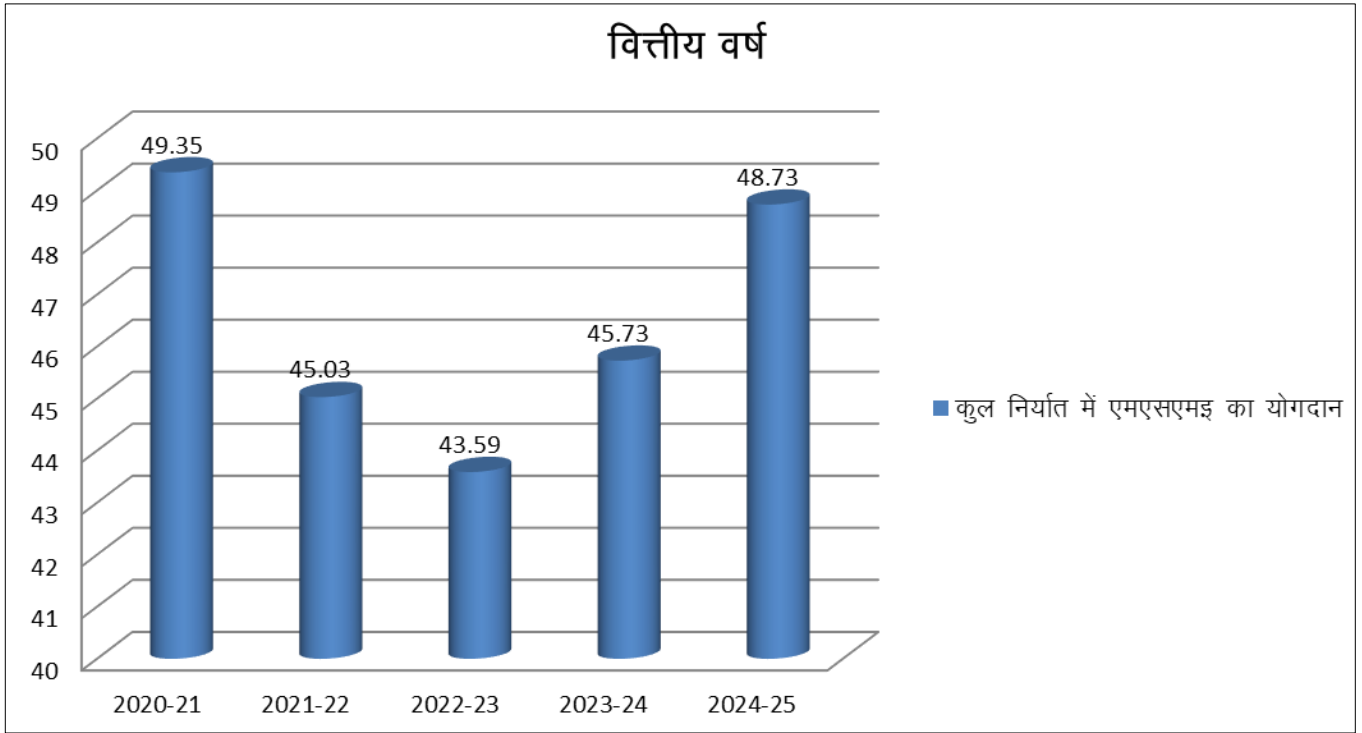
MSME का व्यापार में योगदान वित्तीय वर्ष के अनुसार उत्तराखंड के MSME निर्यात का वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सालाना योगदान 7*30 करोड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध कर

रहा है। MSME के भीतर तीन उपक्षेत्रों से प्रत्येक व्यापार विनिर्माण और अन्य सेवाओं में कुल रोजगार का एक तिहाई रोजगार उत्पन्न कर रहा है। कुल एमएसएमई का 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। जो कुल एमएसएमई के तहत रोजगार का 45 प्रतिशत उत्पन्न करता है।

तालिका संख्या 2

वित्तीय वर्ष	कुल निर्यात में MSME का योगदान
2020-21	49*35
2021-22	45*03
2023-24	43*59
2024-25	45*73
कुल	100

स्रोत: द्वितीय समंक



ग्राफ संख्या 2

तलिका संख्या 2 तथा ग्राफ संख्या 2 के आधार पर स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र की भागीदारी निरंतर महत्वपूर्ण रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में MSME का योगदान लगभग 49.35 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह घट कर 45.03 प्रतिशत रहा तथा 2022-23 में यह और कम होकर 43.59 प्रतिशत पर पहुँचा। वर्ष 2023-24 में MSME का हिस्सा पुनः बढ़कर लगभग 45.73 प्रतिशत हो गया। नवीनतम अवधि 2024-25 में यह योगदान लगभग 48.73 प्रतिशत तक पहुँचता दिखाई देता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तरा-चढ़ाव के बावजूद राज्य के निर्यात ढाँचे में MSME क्षेत्र की भूमिका केन्द्रीय और प्रभावशाली बनी हुई है।

निष्कर्ष

- **रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत:** MSME क्षेत्र में राज्य स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। विशेषकर ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं।
- **निर्यात और उत्पादन में वृद्धि:** हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, जडी-बूटी, पर्यटन आधारित उत्पाद और लघु विनिर्माण इकाइयों ने राज्य के कुल उत्पादन और निर्यात में योगदान बढ़ाया है।
- **महिला और स्वरोजगार को बढ़ावा:** MSME इकाइयों ने महिला उद्यमिता और स्वरोजगार को मजबूत किया है जिससे सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।
- **स्थानीय संसाधनों का उपयोग:** वन उत्पाद, कृषि उपज और पारंपरिक कौशल पर आधारित उद्योगों ने स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया है।
- **आत्म निर्भरता की दिशा में सहयोग:** MSME क्षेत्र राज्य को आत्मनिर्भर और टिकाऊ आर्थिक ढाँचे की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सुझाव

- **सरल ऋण वित्त सुविधा:** छोटे उद्यमियों के लिए कम व्याज दर पर ऋण आसान दस्तावेजीकरण और तेजी स्वीकृति व्यवस्था होनी चाहिए
- **पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज:** पहाड़ी जिलों में परिवहन कच्चे माल और बाजार दूरस्थ की समस्या को देखते हुए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिये जाएँ।
- **क्लस्टर आधारित विकास:** हस्तशिल्प, जडी-बूटी, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन उत्पादों के लिए MSME क्लस्टर विकसित किए जाएँ।

सन्दर्भ सूची

1. उपाध्याय डॉ० वीना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योगों की भूमिका International Journal of Current Science (IJCS PUB), 2024, 14. ISSN: 2250-1770
2. यादव नन्द किशोर: भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का योगदान Internation Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED) ISSN: 2320-8708, 2023, 11.
3. Mukherjee S. Challenges to Indian micro small scale and medium enterprises in the era of globalization. Journal of Global Entrepreneurship Research. 2018;8(28):1-19.
4. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2019), MSME Annual Report 2018-19.
5. Reserve Bank of India, Report of the Expert Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises, 2019.
6. Kimothi SP, Sanjeev Panwar, And Anjani khulbe. Creating wealth from Agricultural Waste Creating Wealth from Agricultural Waste. Indian council of Agricultural Research, New Delhi, 2020, 172.

7. Ghinea C. Waste management models and their application to sustainable management of recyclable waste. Phd thesis, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania, 2012.
8. <https://www.jetir.org>
9. <http://www.jmr.com>
10. <http://cdnbbsr.s3waas.gov.in>